पिपराइच शुगर मिल्स लि.

बनाम

पिपराइच शुगर मिल्स मजदूर यूनियन

[भगवती, वैंकटरामा अय्यर, एस.के.दास व गोविंद मेनन जेजे]

औद्योगिक विवाद-परिभाषा-उद्योग बंद होने से पहले उत्पन्न होने वाले विवाद में दावा-सरकार, यदि सक्षम है तो ऐसे उद्योग बंद होने के बाद निर्णय के लिए अधिसूचना जारी करने में-उद्योग बंद होने पर श्रमिकों की छुट्टी और छंटनी पर छुट्टी-सेवा समाप्ति के लिए मुआवजे का पुरस्कार बंद होने पर-यू.पी. औद्योगिक विवाद अधिनियम (यू.पी. XXVIII सन् 1947), 2, 3-औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का XIV), एस. 2(के).

अपीलकर्ता कंपनी गन्ने की कम आपूर्ति के कारण शहर में अपनी मिलों में पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकी और उसे सरकार से अपनी मशीनरी बेचने की अनुमति मिल गई, लेकिन क्रेता से पट्टे के तहत गन्ने की पेराई जारी रखी। लेन-देन को विफल करने के लिए श्रमिक संघ ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया और कंपनी को अपना संकल्प बताया। पार्टियों के बीच पत्राचार हुआ जिसके दौरान

कंपनी ने श्रमिकों को 25 प्रतिशत भुगतान करने की पेशकश की। बिक्री के मुनाफ़े का भुगतान इस शर्त पर किया जाएगा कि हड़ताल का नोटिस तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। कामगारों ने शर्त पूरी नहीं की और कुछ प्रति-प्रस्ताव दिये। कंपनी ने जोर देकर कहा कि काउंटर प्रस्तावों पर विचार करने और उसके प्रस्ताव को नवीनीकृत करने से पहले शर्त पूरी की जानी चाहिए। हालाँकि कर्मचारी वास्तव में हड़ताल पर नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने हड़ताल का नोटिस वापस नहीं लिया, और मशीनरी को तोड़ने और खरीदार तक पहुंचाने में प्रबंधन के साथ सहयोग नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को भारी नुकसान हुआ। . पट्टे की समाप्ति और उद्योग बंद होने पर, 21 मार्च, 1951 को कंपनी द्वारा कामगारों की सेवाएं विधिवत समाप्त कर दी गईं। इसके बाद, कामगारों ने कंपनी द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर मुनाफे में हिस्सेदारी का दावा किया। पत्राचार और विवाद को यू.पी. सरकार द्वारा निर्णय के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेजा गया था। इसके तहत एक अधिसूचना द्वारा सरकार यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का ट्रिब्यूनल ने माना कि कंपनी अपने द्वारा किए गए प्रस्ताव से बंधी हुई थी और रुपये की राशि प्रदान की गई थी। मुनाफ़े में उनके हिस्से का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्रमिकों

को 45,000 रु. अपील पर औद्योगिक न्यायाधिकरण के फैसले की श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पुष्टि की गई। अपीलकर्ता कंपनी की ओर से यह तर्क दिया गया कि अधिसूचना अधिकारातीत थी, और परिणामस्वरूप संदर्भ और पुरस्कार शून्य थे और पार्टियों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था, इसलिए वह भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं थी।

अभिनिर्धारित किया गया - कि औद्योगिक विवाद की परिभाषा s.2(k) में निहित है, 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम XIV के 2(k) और यू.पी. के औद्योगिक विवाद अधिनियम XXVIII (1947) पर विचार किया गया। किसी उद्योग का अस्तित्व और पार्टियों के बीच नियोक्ता और कर्मचारियों का मौजूदा संबंध और इसलिए, उन अधिनियमों के अर्थ में कोई औद्योगिक विवाद नहीं हो सकता है जहां उद्योग बंद कर दिया गया था, और बंद करना वास्तविक, यदि विवाद इस तरह बंद करने पर या उसके बाद, यदि ऐसा किया जा सकता है, उत्पन्न हुआ।

उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3 में केवल यह आवश्यक था कि सरकार द्वारा उस धारा के तहत एक संदर्भ बनाने से पहले एक औद्योगिक विवाद होना चाहिए और,

परिणामस्वरूप, तत्काल मामले में जहां विवाद में दावा खराब हो, यदि उत्पन्न हुआ हो, उससे पहले। उद्योग बंद करने के लिए सरकार अधिसूचना जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार थी।

भारतीय धातु और धातुकर्म निगम बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण, मद्रास और के.एन. पद्मनाभ अय्यर बनाम द स्टेट ऑफ मद्रास अनुमोदित।

मेसर्स बर्न एंड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता बनाम देयर वर्कमेन, (1955 की सिविल अपील संख्या 395, 11 अक्टूबर 1956 को निर्णय लिया गया), संदर्भित,

हालाँकि, मौजूदा मामले में, चूंकि ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष असंगत और विरोधाभासी थे, अदालत ने पत्राचार दस्तावेजों की जांच की और माना कि यह स्थापित नहीं हुआ कि पार्टियों के बीच कोई समझौता हुआ था जिसके तहत श्रमिकों को किसी भी तरह का अधिकार मुनाफे के हिस्से में दिया जा सकता था और, परिणामस्वरूप, श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए फैसले को रद्द किया जाना चाहिए।

न ही यह पुरस्कार उद्योग बंद होने पर श्रमिकों की सेवाओं की समाप्ति के लिए मुआवजे के रूप में टिकाऊ था क्योंकि इस तरह का

निर्वहन छंटनी पर निर्वहन से अलग था, जिसका अर्थ उद्योग की निरंतरता और केवल अधिशेष का निर्वहन था, और कामगार नहीं थे। वे या तो उस कानून के तहत हकदार हैं जो उनकी रिहाई के दिन था या उस दिन भी था, किसी भी मुआवजे का हकदार हैं।

मेसर्स इंडिया रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के कर्मचारी बनाम इंडिया रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता और मेसर्स बेनेली कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम उनके कर्मचारी प्रतिष्ठित और अस्वीकृत,

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 247

श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण भारत, तृतीय पीठ, लखनऊ के 21 जुलाई, 1953 के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध अपील संख्या कलकत्ता 44/1952

अपीलकर्ता की ओर से जी.सी.माथुर।

एच. जे. उमरीगर, प्रतिवादी के लिए न्याय मित्र।

1956, अक्टूबर 23, न्यायालय का निर्णय दिया गया-

वेंकटराम अय्यर जे.- अपीलकर्ता एक लिमिटेड कंपनी है, जो वर्ष 1932 से गोरखपुर जिले के पिपराइच नामक स्थान पर गन्ना

पेराई का व्यवसाय कर रही थी। 1946 में इसने अपने व्यवसाय का विस्तार करने का निर्णय लिया और उस उद्देश्य से इसे बेच दिया। पुरानी मशीनरी जिसकी प्रतिदिन क्रशिंग क्षमता 160 टन थी, और 650 टन क्षमता वाली एक नई मशीनरी खरीदी। नया संयंत्र 1947 में स्थापित किया गया था, और इसने वास्तव में 1948-49 में काम करना शुरू कर दिया था। इस अवधि के दौरान, चीनी उद्योग गन्ने की कमी के कारण संकट से गुजर रहा था, और परिणामस्वरूप, सरकार ने इसके उत्पादन और आपूर्ति का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। अपीलकर्ता की मिल को जो कोटा आवंटित किया गया था, वह लाभप्रद रूप से काम करने के लिए बहुत छोटा साबित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 1948-49 और 1949-50 में कंपनी को घाटा हुआ, जो अपीलकर्ता के अनुसार 2,67,042-7-4 रुपये तक पहुंच गया।. बड़ी आपूर्ति प्राप्त करने के कई असफल प्रयासों के बाद, प्रबंधन ने 11 मई, 1950 को सरकार को लिखा कि या तो उनका कोटा बढ़ाया जाए या उन्हें मिलें बेचने की अनुमति दी जाए। अक्टूबर, 1950 में, सरकार ने संयंत्र और मशीनरी की बिक्री की अनुमति दी और उसके अनुसार, प्रबंधन ने उन्हें मद्रास की एक पार्टी को बेच दिया। चूँकि उस समय खेती का मौसम चल रहा था, अपीलकर्ता ने क्रेता से चालू सत्र के लिए

मिलों का पट्टा प्राप्त कर लिया और पट्टे की समाप्ति पर उस पर कब्ज़ा देने पर सहमति व्यक्त की। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता क्रेता के साथ बातचीत भी कर रहा था, मशीनरी को नष्ट करने और इसे एकमुश्त विचार के लिए मद्रास में खड़ा करने के लिए, निष्पादन की उम्मीद कर रहा था।

जब श्रमिकों को बिक्री के समझौते के बारे में पता चला, तो इस पर उनकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण थी, और अपने संघ, प्रतिवादी के माध्यम से कार्य करते हुए, उन्होंने लेनदेन को रोकने का फैसला किया, अन्यथा उन्हें रोजगार से बाहर कर दिया जाएगा। सरकार ने मिलों की बिक्री के लिए अपीलकर्ता को दी गई अनुमति रद्द कर दी, और उन्होंने 26 दिसंबर, 1950 को 12 जनवरी, 1951 से हड़ताल पर जाने का एक प्रस्ताव भी पारित किया और अपीलकर्ता को इसकी सूचना दी। इससे पार्टियों के बीच पत्राचार हुआ, और चूंकि यह प्रतिवादी द्वारा लगाए गए और ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे के दावे का आधार है, इसलिए इसे पर्याप्त पूर्णता के साथ निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है। 3 जनवरी, 1951 को प्रबंध निदेशक ने मिल प्रबंधक के माध्यम से 25 प्रतिशत आवंटित करने की पेशकश की। मद्रास पार्टी के साथ बिक्री लेनदेन पर लाभ की कुछ शर्तों पर

और इस शर्त के अधीन कि "हड़ताल की सूचना तुरंत और आज वापस ले ली जाए, ताकि काम की व्यवस्था की जा सके"। इस पर 5 जनवरी, 1951 को संघ का उत्तर इस प्रकार था:

> "प्रबंध निदेशक द्वारा दिए गए आश्वासन के संदर्भ में, आपकी ओर से आपके नंबर 975 दिनांक 4 जनवरी 1951 के तहत हमें सूचित किया गया है, जिसमें हमसे हड़ताल के नोटिस को वापस लेने के लिए कहा गया है, हमें आपको यह बताते हुए खेद है कि हमारी लड़ाई है सरकार के साथ, जो केवल इतने से हल नहीं होती है। हमारे सदस्य किसी भी कीमत पर, हड़ताल, सत्याग्रह, आदि या हमारे महासंघ द्वारा निर्देशित किसी अन्य माध्यम से चीनी मिलों को यहां रखने पर आमादा हैं, अन्यथा कोई आश्वासन नहीं है हजारों प्राणियों के रोजगार का"।

फिर पत्र में कुछ शर्तों पर आपत्ति जताई गई और अंततः यह कहकर समाप्त कर दिया गया कि कर्मचारी इस मामले में सलाह देने के लिए अपने अध्यक्ष काशीनाथ पांडे की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतिवादी द्वारा कुछ शर्तों पर उठाई गई आपत्तियों का जवाब देते हुए, प्रबंधन

ने 8 जनवरी, 1951 को लिखा कि वे उन पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार थे, लेकिन "मुख्य बिंदु" के रूप में हड़ताल के नोटिस को वापस लेने पर जोर दिया। 9 जनवरी, 1951 को काशीनाथ पांडे पिपराइच आए और प्रबंधन से इस मामले पर चर्चा की, जिसके बाद महाप्रबंधक ने 10 जनवरी, 1951 को प्रतिवादी को लिखा कि यदि हड़ताल का नोटिस तुरंत वापस ले लिया जाता है, वह संघ द्वारा उठाए गए निम्नलिखित बिंदुओं को स्वीकार करेगा", और फिर बिंदु निर्धारित किए गए। पत्र ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि मुआवजे की राशि "एक लाख से कम नहीं होगी"। प्रतिवादी ने उसी दिन इसका जवाब दिया कि कर्मचारी इस मामले में काशीनाथ पांडे के "अंतिम आदेश" की प्रतीक्षा कर रहे थे, और प्रबंधन को आश्वासन दिया कि "इस बीच 12 तारीख से हड़ताल खत्म नहीं हो रही है"। इसके बाद, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी की बात नहीं सुनी, हड़ताल भी नहीं हुई और पेराई जनवरी 1951 के अंत तक चलती रही, जब तक कि सीज़न समाप्त नहीं हो गया। इस अपील में हमारे निर्धारण के लिए उठने वाले बिंदुओं में से एक यह है कि क्या इस पत्राचार पर एक निष्कर्ष निकाला गया और बाध्यकारी समझौता हुआ था कि श्रमिको को बिक्री

लेनेदन पर लाभ का अपीलकर्ता को 25 प्रतिशत का भुगतान करना होगा।

कथन को जारी रखने के लिए, पेराई सत्र के साथ पट्टा समाप्त हो गया था, क्रेता मिलों की डिलीवरी लेने के लिए पिपराइच आया था और मशीनरी को नष्ट करने और वहां स्थापित करने के लिए मद्रास ले जाने की व्यवस्था करने के लिए आया था। अपीलकर्ता, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, एकमुश्त विचार के लिए निराकरण कराने के लिए बातचीत कर रहा था, उसने पाया कि उसके काम करने वाले हमेशा की तरह इसके प्रति शत्रुतापूर्ण थे, और उसने काम में मदद करने से इनकार कर दिया। अपने लिखित बयान में प्रतिवादी की भाषा को अपनाने के लिए, "उन्होंने अपनी कब्र खोदने की भावना से इनकार कर दिया"। मशीनरी को नष्ट करने में सहयोग करने के असफल प्रयासों के बाद, प्रबंधन ने 28 फरवरी, 1951 को निम्नलिखित नोटिस लगाया:

"पिपराइच शुगर मिल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि हमने सरकार की अनुमति के तहत अपनी मिल मद्रास पार्टी को बेच दी है। पार्टी इसे तोड़ने के लिए आ गई है। समझौते की शर्तों के तहत, हम इस काम में उनकी मदद करने के लिए बाध्य हैं।"

इसलिए श्रमिकों को पता होना चाहिए कि हम यह उपकार कर सकते हैं कि हम यहां निराकरण और मद्रास में निर्माण का ठेका ले सकते हैं और श्रमिकों को काम पर रख सकते हैं और क्रेताओं से उन्हें उनकी चिंता में उपलब्ध कराने का अनुरोध कर सकते हैं। इसलिए यह सूचित किया जाता है कि जो श्रमिक इसके लिए तैयार नहीं हैं सहयोग करने पर वे स्वयं को 1 मार्च 1951 से सेवा मुक्त समझें। श्रमिकों को पन्द्रह दिन का नोटिस दिया जाता है। जो रुकावटें पैदा करने से वे उन लाभों से वंचित हो जायेंगे जिनका वादा किया गया था।"

वे जो यूनियन मिलों के स्थानांतरण की संभावना से सहमत नहीं हो सकी और 4 मार्च, 1951 को काशीनाथ पांडे ने सरकार को एक पत्र लिखकर धमकी दी कि यदि मिलों को पिपराइच से स्थानांतरित किया गया तो वे भूख हड़ताल पर चले जायेंगे। इस प्रकार कर्मचारी 28 फरवरी, 1951 के नोटिस में निहित शर्तों को स्वीकार करने के मूड में नहीं थे, और इसलिए, प्रबंधन को 14 मार्च, 1951 को निम्नलिखित शर्तों में एक और नोटिस जारी करना पड़ा:

"जबकि कर्मचारियों को पहले ही सूचित कर दिया गया है कि हमने अपना पूरा संयंत्र मद्रास की एक पार्टी को बेच दिया है जो मशीनों का कार्यभार संभालने के लिए आई है और हमें संयंत्र को 15-

3-1951 से खरीददारों को सौंपना है और इस प्रकार हमारे श्रमिकों के लिए कोई काम नहीं होगा और जबकि मजदूर संघ ने मद्रास में निराकरण और निर्माण के काम में श्रमिकों को शामिल करने के हमारे सुझाव को पहले ही अस्वीकार कर दिया है। अब हमारे नोटिस दिनांक 28-2-1951 के अनुसरण में, यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित श्रमिकों को 1-3-1951 से सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है, बशर्ते कि उन्हें 15 दिन का वेतन दिया जाए। श्रमिकों को इसके द्वारा 15 और 16 तारीख को अपना 15 दिन का वेतन लेने के लिए कहा जाता है।

अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को भेजे गए 16 मार्च 1951 के नोटिस से ऐसा प्रतीत होता है कि 14 मार्च 1951 को नोटिस जारी होने के बाद काशीनाथ पांडे ने प्रबंधन के साथ चर्चा की, जिसके परिणामस्वरूप समाप्ति की तारीख तय की गई पिपराइच कारखाने के भविष्य के कार्यक्रम पर सरकार के निर्णय के लंबित रहने तक श्रमिकों की सेवा अवधि 15 मार्च से 21 मार्च तक बढ़ा दी गई थी", श्रमिक अपनी ओर से "उक्त तिथि के बाद मिल को तोड़ने का काम करने" पर सहमत हुए। "लेकिन सरकार ने 21 मार्च, 1951 के अपने पत्र द्वारा मशीनरी की बिक्री में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, और

ऊपर हुई समझ के अनुसार, श्रमिकों को मेट को नष्ट करने में अपीलकर्ता के साथ सहयोग करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, और उसके बाद, 28 फरवरी, 1951 के नोटिस के अनुसार कार्य किया और 14 मार्च 1951 को प्रबंधन ने उन्हें विधिवत सेवामुक्त कर दिया। अपीलकर्ता की अनुबंध लेने में असमर्थता को देखते हुए, क्रेता ने श्रमिकों के साथ सीधी बातचीत की और 1-4-1951 को मशीनरी को नष्ट करने के लिए उनके साथ एक समझौता किया। इसका शुद्ध परिणाम यह हुआ कि अपीलकर्ता ने एक अनुबंध खो दिया, जिस पर, जैसा कि प्रतिवादी ने स्वीकार किया, उसे कम से कम 2 लाख रुपये का लाभ प्राप्त होता। मशीनरी को नष्ट करने के लिए क्रेता के साथ सीधे अनुबंध का लाभ उठाते हुए, श्रमिकों ने अपना ध्यान अपीलकर्ता की ओर लगाया, और 3 जनवरी, 1951 और 10 जनवरी, 1951 के पत्रों के आधार पर, 19 अप्रैल, 1951 को इसे एक नोटिस भेजा गया, जिसमें "मशीनरी की बिक्री पर लाभ का 25 प्रतिशत श्रम-हिस्सा" श्रमिकों के बीच वितरित करने के लिए कहा गया। 19 जून, 1951 को अपने पत्र द्वारा, अपीलकर्ता ने दावे को खारिज कर दिया, और कहा:

"फिर हम आपको अपने दिनांक 27-2-1951 के नोटिस का भी हवाला देते हैं जिसमें हमने लेबर से हमारे साथ सहयोग करने की अपील की थी ताकि हम यहां पिपराइच में डिस्मेंटल और एतिकोप्पाका में निर्माण का ठेका ले सकें और निश्चित रूप से कहा था कि जो लोग सहयोग नहीं करते, उन्हें अपने आप को बरी समझना चाहिए। इससे हमें श्रम की मांग को पूरा करने के लिए अच्छी बचत मिल जाती, लेकिन चूंकि आपने हमारी अपील और नोटिस के बावजूद सहयोग करने से इनकार कर दिया, इसलिए हमें नुकसान उठाना पड़ा। एक भारी क्षति, जिसके लिए आप सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं"।

इसके बाद, प्रतिवादी ने मामले में कार्रवाई करने के लिए सरकार से गुहार लगाई और नतीजा यह हुआ कि 16 नवंबर, 1951 को यूपी सरकार ने 1947 के यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम XXVIII की धारा 3 के तहत एक अधिसूचना जारी की, जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में जाना जाता है।, निम्नलिखित विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए संदर्भित करते हुए:

"क्या पिपराइच शुगर मिल्स लिमिटेड, पिपराइच, जिला गोरखपुर नामक कंपनी द्वारा श्रमिकों की सेवाएं, यदि हां, तो कितने, उनके उचित दावों का निपटान किए बिना और गलत तरीके से समाप्त कर दी गईं; और यदि हां, तो किस राहत के लिए क्या संबंधित कामगार इसके हकदार हैं?"

28 फरवरी, 1952 के अपने पुरस्कार द्वारा औद्योगिक ट्रायल ट्रिब्यूनल ने सबसे पहले माना कि अपीलकर्ता द्वारा व्यवसाय बंद करना और मशीनरी की बिक्री उचित थी, क्योंकि उसे लगातार घाटा हो रहा था और गन्ने की आपूर्ति की स्थिति में सुधार की कोई तत्काल संभावना नहीं थी, इसलिए काम करने वालों का आचरण अनुचित था और उन्हें मुआवजे से वंचित करना था, लेकिन 3 और 10 जनवरी, 1951 के पत्रों में 25 प्रतिशत का भुगतान करने का वादा शामिल था। मिलों की बिक्री से प्राप्त लाभ प्रबंधन के लिए बाध्यकारी था। इसने अपीलकर्ता के तर्क को खारिज करते हुए आगे कहा कि 16 नवंबर, 1951 की अधिसूचना सक्षम थी, इसके बावजूद कि उस तारीख को व्यवसाय बंद कर दिया गया था। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने मिलों की बिक्री पर अपीलकर्ता द्वारा किए गए मुनाफे का पता लगाने

के लिए कार्रवाई की, और माना कि रु. 45,000 25 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। शुद्ध लाभ का भुगतान श्रमिकों को किया जाना था। प्रबंधन ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने 21 जुलाई, 1953 के अपने आदेश द्वारा इसकी पुष्टि की। मामला अब अनुच्छेद 136 के तहत अपील में हमारे सामने आता है। चूंकि अपील में महत्व के प्रश्न उठाए गए थे, और चूंकि प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व नहीं था इसलिए हमने श्री उमरीगर से हमारी सहायता करने का अनुरोध किया, और हम उनके विद्वतापूर्ण और व्यापक तर्क के लिए उनके आभारी हैं।

अपील के समर्थन में दो तर्क दिए गए हैं :-

(1) अधिसूचना दिनांक 16 नवंबर,1951, विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायनिर्णयन के लिए संदर्भित करना अधिकारातीत है, और उसमें संदर्भ और पुरस्कार परिणामतः शून्य हैं; और (2) बिक्री लेनदेन में श्रमिकों को लाभ का कोई हिस्सा देने के लिए अपीलकर्ता द्वारा कोई निष्कर्ष निकाला गया या बाध्यकारी समझौता नहीं किया गया था और इसलिए पुरस्कार गुण-दोष के आधार पर खराब है।

पहला तर्क लेते हुए, कानून का वह प्रावधान जिसके तहत राज्य द्वारा 16 नवंबर, 1951 की अधिसूचना जारी की गई थी, अधिनियम की धारा 3 है, जो इस प्रकार है:

> "यदि राज्य सरकार की राय में, सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा सुनिश्चित करने या रखरखाव के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है सार्वजनिक व्यवस्था या समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाएँ, या रोज़गार बनाए रखने के लिए, यह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, समर्थक बना सकता है-
>
> (डी) किसी भी औद्योगिक विवाद को आदेश में दिए गए तरीके से सुलह या न्यायनिर्णयन के लिए संदर्भित करने के लिए"।

एक "औद्योगिक विवाद", जैसा कि इसमें परिभाषित किया गया है। 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम XIV के 2(के) और धारा 2 के बल पर, यह परिभाषा अधिनियम पर लागू होती है- "नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच, या नियोक्ताओं और कामगारों के बीच, या कामगारों और कामगारों के बीच किसी भी विवाद या

मतभेद का मतलब है, जो किसी व्यक्ति के रोजगार या गैर-रोजगार या रोजगार की शर्तों या श्रम की शर्तों से जुड़ा है। अब, अपीलकर्ता का तर्क यह है कि यह धारा के तहत राज्य द्वारा अपनी शक्ति के प्रयोग से पहले की एक शर्त है। अधिनियम की धारा 3 के तहत कोई औद्योगिक विवाद होना चाहिए, कि इस परिभाषा के अनुसार कोई औद्योगिक विवाद नहीं हो सकता है, जब तक कि नियोक्ता और कर्मचारी का कोई संबंध न हो; वर्तमान मामले में, चूँकि अपीलकर्ता ने अपनी मिलें बेच दीं, अपना व्यवसाय बंद कर दिया और 21 मार्च, 1951 को श्रमिकों को छुट्टी दे दी, और उन्हें स्थायी आदेशों के अनुसार जो भी बकाया था, उसका पूरा भुगतान कर दिया, उसके बाद कोई सवाल ही नहीं था। नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच संबंध, तदनुसार 16 नवंबर, 1951 को अधिसूचना की तारीख पर कोई औद्योगिक विवाद नहीं था, और इसलिए यह अक्षम था। इस स्थिति के समर्थन में भारतीय धातु और धातुकर्म निगम बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण, मद्रास) में अवलोकन पर भरोसा रखा गया था कि "औद्योगिक विवाद" की परिभाषा जारी रखने की परिकल्पना करती है। उद्योग का अस्तित्व, और के.एन. पद्मनाभ अय्यर बनाम मद्रास राज्य में निर्णय पर कि ऐसे व्यवसाय के संबंध में कोई औद्योगिक

विवाद नहीं हो सकता, जो अस्तित्व में नहीं था। इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि अधिनियम की पूरी योजना यह मानती है कि अस्तित्व में एक उद्योग है और फिर उस उद्योग में कोई विवाद उत्पन्न होने पर उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों के लिए प्रावधान करता है। इस प्रकार, तालाबंदी, हड़ताल, छंटनी, छंटनी, सुलह और न्यायनिर्णयन कार्यवाही से संबंधित अधिनियम के प्रावधान, जिस अवधि के दौरान पुरस्कार लागू होने हैं, उनका अर्थ केवल तभी है जब वे मिल्स मसदो का उल्लेख करते हैं उद्योग जो चल रहा है, न कि जो बंद है।

मेसर्स बर्न एंड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता बनाम उनके कर्मकार इस न्यायालय ने पाया कि सभी श्रम कानूनों का उद्देश्य सबसे पहले श्रमिकों को उचित शर्तें सुनिश्चित करना था, और दूसरा नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच विवादों को रोकना था, ताकि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और व्यापक हित प्रभावित न हों। जनता को परेशानी न हो. इन दोनों वस्तुओं की पूर्ति केवल मौजूदा उद्योग में ही हो सकती है, मृत उद्योग में नहीं। इसलिए भारतीय धातु और धातुकर्म निगम बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण, मद्रास और के.एन. पद्मनाभा अय्यर बनाम मद्रास राज्य में व्यक्त विचार यह है कि

औद्योगिक विवाद जिस पर अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं जो मौजूदा उद्योग से उत्पन्न होता है वह स्पष्ट रूप से सही है। इसलिए, जहां व्यवसाय बंद कर दिया गया है और यह या तो स्वीकार कर लिया गया है या पाया गया है कि बंद करना वास्तविक और प्रामाणिक है, तो उसके संदर्भ में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, जैसा कि के.एन. पद्मनाभ अय्यर बनाम मद्रास राज्य में आयोजित किया गया था, माना जाएगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे से बाहर हैं। और ऐसा तब होगा, जब नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच व्यवसाय बंद होने के बाद कोई विवाद उत्पन्न होता है - यदि ऐसी कल्पना की जा सकती है।

ऊपर बताए गए सिद्धांतों के आलोक में, हमें विवाद की प्रकृति की जांच करनी चाहिए जो कि विवादित अधिसूचना के तहत संदर्भ का विषय-वस्तु है। कामगारों का दावा है कि प्रबंधन द्वारा 3 जनवरी, 1951 और 10 जनवरी, 1951 के अपने पत्रों में किया गया वादा एक बाध्यकारी समझौता है और वे उसके अनुसार भुगतान पाने के हकदार हैं। अब, यदि यह विवाद अच्छी तरह से स्थापित है, तो यह विवाद एक दावे से संबंधित है जो उत्पन्न हुआ जबकि उद्योग अस्तित्व में था और उन व्यक्तियों के बीच था जो नियोक्ता और कर्मचारियों के

रिश्ते में थे, और यह स्पष्ट रूप से एक औद्योगिक विवाद होगा जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया है। लेकिन अपीलकर्ता के लिए यह तर्क दिया गया है कि फिर भी, 16 नवंबर, 1951 की अधिसूचना अक्षम होगी क्योंकि उद्योग उस तारीख से पहले बंद हो चुका था, और इसलिए उस समय नियोक्ता और कर्मचारी के बीच कोई संबंध नहीं था। दूसरे शब्दों में, धारा 3 के तहत संदर्भ देने की राज्य की शक्ति, अपीलकर्ता के अनुसार, न केवल मौजूदा उद्योग में उत्पन्न होने वाले विवाद पर निर्भर करेगी, बल्कि इसके अलावा, उस उद्योग के निरंतर अस्तित्व पर भी निर्भर करेगी। हमें अधिनियम की धारा 3 की भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो संदर्भ देने की राज्य की शक्ति पर इस अतिरिक्त सीमा को लागू करने के लिए उचित हो। उस धारा में अन्य शर्तों के अलावा, जिनसे हमें कोई सरोकार नहीं है, केवल यह आवश्यक है कि संदर्भ देने से पहले एक औद्योगिक विवाद होना चाहिए, और हमने माना है कि यदि यह किसी से उत्पन्न होता है तो यह एक औद्योगिक विवाद होगा। मौजूदा उद्योग. यदि वह शर्त पूरी हो जाती है, तो उस धारा के तहत कार्रवाई करने के लिए राज्य की क्षमता पूरी हो जाती है, और यह तथ्य कि उद्योग बंद हो गया है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। हमारी राय में, किसी भी

अन्य निर्माण के परिणामस्वरूप गंभीर विसंगतियाँ और गंभीर अन्याय होगा। यदि अनुचित तरीके से बर्खास्त किया गया कोई कामगार औद्योगिक विवाद खड़ा करता है, और सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने से पहले उद्योग बंद कर दिया जाता है, तो उस अधिकार का क्या होगा जो अधिनियम उसे उचित राहत के लिए देता है, यदि अधिनियम जल्द ही हवा में उड़ जाता है क्योंकि उद्योग बंद है? यदि अपीलकर्ता का तर्क सही है, तो ऐसे नियोक्ता को क्या रोका जा सकता है जो अच्छे और व्यावसायिक कारणों से अपने व्यवसाय को बड़े पैमाने पर अनुचित श्रम प्रथाओं, उत्पीड़न और गलत बर्खास्तगी में शामिल होने से बंद करने का इरादा रखता है, और उद्योग बंद करके उसके परिणामों से बच रहे हैं? हम सोचते हैं कि धारा 3 का वास्तविक अर्थ उस धारा के तहत संदर्भ देने की राज्य की शक्ति उस तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जानी चाहिए न कि उस तारीख के आधार पर और परस्पर विरोधी निष्कर्ष, और परिणामस्वरूप हमारे लिए यह निर्धारित करना आवश्यक हो गया है कि इसके कौन से निष्कर्षों को सामग्री द्वारा समर्थित के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। हम 3 जनवरी 1951 के पत्र से शुरू करते हैं। जिसमें प्रबंधन ने काम करने वालों को बिक्री लेनदेन के मुनाफे का 25 प्रतिशत

भुगतान करने की पेशकश की। यह स्पष्ट रूप से इस शर्त के अधीन था कि हड़ताल "तुरंत और आज ही" समाप्त कर दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं किया गया. दूसरी ओर, प्रतिवादी ने 5 जनवरी, 1951 को लिखे अपने पत्र में कुछ प्रति-प्रस्ताव दिए और प्रबंधन ने 8 जनवरी, 1951 को जवाब दिया कि वह अपनी शर्तों पर पुनर्विचार करेगा, बशर्ते हड़ताल नोटिस वापस ले लिया जाए। इस प्रकार, 3 जनवरी, 1951 के पत्र में शामिल प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया और समाप्त हो गया। फिर 10 जनवरी, 1951 को प्रबंधन ने अपने प्रस्ताव को फिर से इस शर्त पर नवीनीकृत किया कि हड़ताल का नोटिस तुरंत वापस ले लिया जाए। प्रतिवादी ने नोटिस वापस लेने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया, और 10 जनवरी, 1951 को अपने उत्तर में यह स्पष्ट कर दिया कि वह अंतिम निर्णय पर आने के लिए काशीनाथ पांडे की प्रतीक्षा कर रहा था। संघ की ओर से कोई दूर संचार नहीं था। हम यह नहीं देखते हैं कि इस पत्राचार पर यह कैसे माना जा सकता है कि पार्टियों के बीच एक निष्कर्ष निकाला गया समझौता था, और ट्रिब्यूनल ने स्वयं यही दृष्टिकोण अपनाया जब उसने देखा कि "कोई अंतिम समझौता नहीं किया जा सका और परिणामस्वरूप प्रबंधन ने 28 फरवरी 1951 को एक नोटिस दिया। लेकिन फिर, यह देखा गया कि, वास्तव में,

कामगार 12 जनवरी, 1951 को हड़ताल पर नहीं गए, और 28 फरवरी, 1951 को सेवामुक्ति का नोटिस मिलने तक सेवा में बने रहे, यह विचाराधीन था। समझौते द्वारा किया गया वादा, जिसे इसलिए सेवा की अवधि माना जाना चाहिए, और परिणामस्वरूप "3 और 10 जनवरी 1951 के पत्रों में निहित प्रबंधन का वादा, एक बाध्यकारी समझौता है जिसके तहत मिलें बंद होने पर कामगार अपनी सेवाएं समाप्त करने के लिए मुआवजे के हकदार हैं।" यह तर्क विचार की उलझन पर आधारित है। सवाल यह है कि क्या किये गये वादे पर कोई विचार हुआ 3 जनवरी और 10 जनवरी 1951 के अपने पत्रों में प्रबंधन केवल तभी उठता है जब पत्रों में शामिल प्रस्ताव प्रतिवादी द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, ताकि एक समझौते में तब्दील हो सके। और यदि पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था, जैसा कि ट्रिब्यूनल ने स्वयं माना था, तो आगे यह प्रश्न नहीं उठता कि क्या यह विचार द्वारा समर्थित था, न ही इसके सेवा की शर्तों में से एक बनने का कोई प्रश्न होगा।

यह तर्क दिया गया कि यद्यपि हड़ताल वापस लेने का औपचारिक प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था, वास्तव में कोई हड़ताल नहीं थी, और इसे आचरण द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के रूप में

लिया जाना चाहिए। यह अपीलकर्ता द्वारा अपेक्षित स्वीकृति नहीं होगी, और यह अकेले ही प्रतिवादी के विवाद को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन यह विवाद गुण-दोष के आधार पर भी विफल होना चाहिए। 10 जनवरी, 1951 को लिखे अपने पत्र में, प्रतिवादी ने यह कहते हुए कि 12 तारीख को हड़ताल नहीं हो रही थी, यह स्पष्ट कर दिया कि यह संघ के अंतिम निर्णय के लिए लंबित था। यह स्पष्ट रूप से प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं है। मामला यहीं शांत नहीं होता. यह याद रखना चाहिए कि हड़ताल का उद्देश्य रोज़गार की शर्तों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ कुछ नहीं था, बल्कि उससे जुड़ा कुछ था। इसका उद्देश्य मिलों को पिपराइच से मद्रास तक जाने से रोकना था। जब प्रबंधन ने 25 फीसदी हिस्सेदारी छोड़ने की पेशकश की. बिक्री लेन-देन के मुनाफ़े का, इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से श्रमिकों के विरोध को निरस्त्र करना और मशीनरी को नष्ट कर क्रेता को शांतिपूर्वक सौंपना था। क्या कामगार कभी इस पर सहमत हुए? 5 मार्च, 1951 को काशीनाथ पांडे ने सरकार को लिखा कि यदि मिलों को पिपराइच से स्थानांतरित किया गया, तो वह भूख हड़ताल पर चले जायेंगे। सरकार द्वारा उन्हें सूचित करने के बाद भी कि बिक्री में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, श्रमिकों ने मशीनरी को तोड़ने में

प्रबंधन के साथ सहयोग नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को इसके संदर्भ में अनुबंध छोड़ना पड़ा और रु. 2 लाख का मुनाफा हारना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि काम करने वालों ने अपीलकर्ता को निराकरण का ठेका लेने से सफलतापूर्वक रोका, स्वयं इसमें क्रेता के साथ सीधे प्रवेश किया और निस्संदेह उस लाभ का एक हिस्सा, यदि पूरा नहीं, तो रोक लिया, जो अपीलकर्ता ने अर्जित किया होगा। इन तथ्यों पर टिके रहना असंभव है कि पार्टियों के बीच अपीलकर्ता को बिक्री लेनदेन के लाभ का हिस्सा देने के लिए बाध्य करने वाला एक समझौता हुआ था।

श्री उमरीगर ने आगे यह तर्क दिया कि भले ही बिक्री लेनदेन पर श्रमिकों को लाभ का हिस्सा देने के लिए प्रबंधन द्वारा कोई समझौता नहीं किया गया था, फिर भी ट्रिब्यूनल के पास क्षेत्र के लिए मुआवजा देने का अधिकार होता। उनकी सेवाओं का निष्कासन, इसे छँटनी के रूप में मानना, और रुपये का मुआवजा देना। 45,000 जो प्रबंधन ने स्वयं सुझाया था, उस स्तर पर बनाए रखा जा सकता है। यह तर्क मानता है कि किसी व्यवसाय के बंद होने पर श्रमिकों की सेवाओं की समाप्ति, छंटनी है। लेकिन छँटनी अपनी सामान्य स्वीकृति में दर्शाती है कि व्यवसाय स्वयं जारी रखा जा रहा है लेकिन

कर्मचारियों या श्रम बल के एक हिस्से को अधिशेष के रूप में छुट्टी दे दी जाती है और बंद होने के परिणामस्वरूप सभी श्रमिकों की सेवाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए व्यवसाय को छंटनी के रूप में उचित रूप से वर्णित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, श्री उमरीगर द्वारा यह तर्क दिया गया है कि 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम XIV की धारा 2(00) में छंटनी की परिभाषा इतनी व्यापक है कि व्यवसाय बंद होने पर परिणामी छुट्टी को शामिल किया जा सकता है, और धारा 25-एफ के तहत, उसके लिए मुआवजा दिया जा सकता है। अपीलकर्ता की ओर से हमारा ध्यान जे.के.होजरी फेक्ट्री बनाम लेबर अपील ट्रिब्यूनल की ओर आकर्षित किया लेकिन श्री उमरीगर का तर्क है कि यह ग़लत है। हम इस प्रश्न पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं समझते, क्योंकि अधिनियम XIV 1947 की धारा 2(00) में "छंटनी" की परिभाषा और उसमें धारा 25-F को औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम संख्या XLIII, 1953 द्वारा सम्मिलित किया गया था और हमने मेसर्स बर्न एंड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता बनाम में आयोजित किया है कि इस अधिनियम का कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं है। इसलिए वर्तमान अपील के पक्षकारों के अधिकारों का निर्णय

कानून के अनुसार किया जाना चाहिए जैसा कि 21 मार्च, 1951 को था, जब श्रमिकों को छुट्टी दे दी गई थी।

मेसर्स इंडिया रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के कर्मचारी बनाम मेसर्स इंडिया रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता और मेसर्स बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम उनके कर्मचारी मामले में निर्णयों के आधार पर अगली दलील दी गई। 1953 के अधिनियम XLIII के अधिनियमन से पहले भी, ट्रिब्यूनल ने इस दृष्टिकोण पर काम किया था कि छंटनी में व्यवसाय बंद करने पर छुट्टी शामिल थी, और उस स्तर पर मुआवजा दिया था और वर्तमान मामले में ट्रिब्यूनल का पुरस्कार हो सकता है उस दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है और परेशान नहीं किया जाना चाहिए। मेसर्स इंडिया रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के कर्मचारी बनाम मेसर्स इंडिया रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के मामले में, ट्रिब्यूनल ने पृष्ठ 576 पर निम्नानुसार टिप्पणी की:

"आम तौर पर छंटनी का मतलब श्रम बल के केवल अधिशेष हिस्से की सेवा से छुट्टी है, लेकिन बंद होने की स्थिति में पूरी श्रम शक्ति को हटा दिया जाता है। संक्षेप में बंद करने और सामान्य छंटनी के बीच का अंतर केवल डिग्री का है। जैसा कि छंटनी के

मामले में होता है इसलिए बंद होने की स्थिति में कामगार अपनी नौकरियां बंद करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। दोनों ही मामलों में, जिसे छंटनी राहत के रूप में मुआवजा कहा जाता है, वह स्वीकार्य होना चाहिए।

हम इन टिप्पणियों से सहमत होने में असमर्थ हैं। यद्यपि छंटनी और कारोबार बंद होने दोनों ही स्थितियों में श्रमिकों को बर्खास्त किया जाता है, मुआवजा कानून के तहत दिया जाना है, न कि छुट्टी के लिए बल्कि छंटनी पर छुट्टी के लिए, और यदि, जैसा कि माना जाता है, सामान्य भाषा में छंटनी का मतलब है, अधिशेष का निर्वहन, इसमें व्यवसाय बंद होने पर निर्वहन शामिल नहीं हो सकता है। इसके अलावा, मेसर्स इंडिया रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता बनाम मेसर्स इंडिया रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के कर्मचारी मामले में व्यवसाय बंद करने का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि वहाँ जो हुआ वह यह था कि कंपनी की एक इकाई, जो कलकत्ता में थी, बंद कर दी गई थी और यह छंटनी का मामला होगा, और ऊपर उद्धृत टिप्पणियाँ पूरी तरह से आपत्तिजनक थीं। हालाँकि, मेसर्स बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम उनके कर्मचारी मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा बिना

चर्चा के उन्हें उद्धृत किया गया और उनका पालन किया गया, जिसे आगे पी 27 पर अंकित किया गया।

"इस प्रकार, बंद करना उचित था या नहीं, जिन श्रमिकों ने अपनी नौकरी खो दी है, उन्हें किसी भी स्थिति में मुआवजा मिलेगा। यदि यह प्रामाणिक नहीं था या उचित नहीं था, तो यह हो सकता है कि मुआवजे का माप इससे बड़ा होगा।

ऊपर दिए गए कारणों से, हम इन टिप्पणियों से सहमत नहीं हो सकते। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि मेसर्स बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम उनके कर्मचारी मामले में, व्यवसाय बंद नहीं हुआ था, बल्कि एक समाचार पत्र प्रकाशन कंपनी द्वारा कलकत्ता इकाई को बंद किया गया था, जिसका मुख्यालय बॉम्बे में था। तदनुसार हमें इस विवाद को भी खारिज करना चाहिए। हमें यह जोड़ना चाहिए कि ट्रिब्यूनल की राय थी कि, समझौते के अलावा, श्रमिकों को उनके आचरण को देखते हुए मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए, और हम इससे पूरी तरह सहमत हैं। और जैसा कि हमने समझौते के विरुद्ध पाया है, हमें इस अपील को स्वीकार करना चाहिए, और ट्रिब्यूनल द्वारा श्रमिकों को दिए गए मुआवजे के फैसले

को रद्द करना चाहिए। इन परिस्थितियों में, पार्टियाँ अपना सारा खर्च स्वयं वहन करेंगी।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **राजेश गुप्ता** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।